भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5160
02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

पीएलएफएस रिपोर्ट

5160. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)प्रतिवेदनों के मुख्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं और पीएलएफएस की वर्तमान स्थिति क्या है और भारत में विशेषकर युवाओं और महिलाओं में बेरोजगारी दर के संबंध में इसके नवीनतम निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में और अधिक बारंबार और विस्तृत सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएलएफएस आंकड़ों के संग्रहण और रिपोर्टिंग की समयबद्धता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) जनवरी, 2025 से मासिक पीएलएफएस प्रतिवेदनों को अपनाने के लिए प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(च) पीएलएफएस प्रतिवेदनों के मासिक जारी होने से रोजगार के मुद्दों के समाधान हेतु कार्यनीतियां बनाने में किस प्रकार सहायता मिलने की आशा है; और

(छ) क्या 2014-15 से अब तक श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है और पीएलएफएस के मासिक प्रकाशन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

क): जुलाई 2021- जून 2022 से जुलाई 2023- जून 2024 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से निम्नलिखित अनुमान दिए गए हैं:

- ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे तालिका में दी गई है:

पीएलएफएस 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण और शहरी संयुक्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल संकेतक (प्रतिशत में)

अखिल भारत

सर्वेक्षण (वर्ष)	सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस)के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में)		
	ग्रामीण	शहरी	(ग्रामीण +शहरी)
पीएलएफएस, 2021-22	42.2	39.0	41.3
पीएलएफएस, 2022-23	43.4	39.8	42.4
पीएलएफएस, 2023-24	46.8	41.0	45.1

सर्वेक्षण (वर्ष)	सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार डब्लयूपीआर (प्रतिशत में)		
	ग्रामीण	शहरी	(ग्रामीण +शहरी)
पीएलएफएस, 2021-22	40.8	36.6	39.6
पीएलएफएस, 2022-23	42.3	37.7	41.1
पीएलएफएस, 2023-24	45.6	38.9	43.7

सर्वेक्षण (वर्ष)	सामान्य स्थिति के अनुसार यूआर (प्रतिशत में) (पीएस+एसएस)		
	ग्रामीण	शहरी	(ग्रामीण +शहरी)
पीएलएफएस, 2021-22	3.3	6.3	4.1
पीएलएफएस, 2022-23	2.4	5.4	3.2
पीएलएफएस, 2023-24	2.5	5.1	3.2

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24

नोट: 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 – जून 2024 की अवधि से है, इसी प्रकार 2022-23 और 2021-22 के लिए भी यही अवधि लागू होगी।

• युवाओं (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्ति) और महिलाओं के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

पीएलएफएस 2023-24 से युवाओं (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्ति) और महिलाओं के लिए ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)

अखिल भारत

क्षेत्र	सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार यूआर (प्रतिशत में)	
	युवा (15-29 वर्ष की आयु के व्यक्ति)	सभी आयु वर्ग की महिलाएं
ग्रामीण	8.5	2.1
शहरी	14.7	7.1
(ग्रामीण +शहरी)	10.2	3.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24
नोट: 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि से है

(ख), (ड़), (च), (छ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) प्रमुख श्रम बल संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में बेरोजगारी दर (यूआर) के तिमाही अनुमान प्रदान कर रहा है, साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में रोजगार और बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों के वार्षिक अनुमान भी प्रदान कर रहा है। समग्र देश स्तर पर अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए और उप-राज्य स्तर पर रोजगार बेरोजगारी संकेतक तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जनवरी *2025* से पीएलएफएस के नमूना डिजाइन को नया रूप दिया गया है। सर्वेक्षण निष्पादन में संबंधित परिवर्तनों के साथ संशोधित नमूना डिजाइन के परिणामस्वरूप पीएलएफएस प्रसार में निम्नलिखित अद्यतनीकरण होगा:

i. वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) दृष्टिकोण के अनुरूप अखिल भारत स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमानों की उपलब्धता।
ii. तिमाही अनुमानों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों और इस प्रकार पूरे देश के लिए रोजगार बेरोजगारी संकेतकों के तिमाही अनुमानों की उपलब्धता।
iii. श्रम बाजार संकेतकों के जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने का प्रावधान

अप्रैल, 2017 से इसकी स्थापना के बाद से लागू पीएलएफएस का प्रतिदर्श डिजाइन बंद कर दिया गया है और प्रतिदर्शों के चयन और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रोटेशनल पैनल डिजाइन को क्रियान्वित करने के लिए जनवरी 2025 से नवीन प्रतिदर्श डिजाइन लागू किया गया है।

पीएलएफएस अनुमानों को मासिक रूप से जारी करने की योजना, समग्र देश स्तर पर अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के मासिक अनुमानों से समय रहते नीतिगत हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

जुलाई 2017- जून 2018 से जुलाई 2023- जून 2024 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण शहरी संयुक्त क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के अनुमान नीचे तालिका में दिए गए हैं:

पीएलएफएस से ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण और शहरी संयुक्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में)

अखिल भारत

सर्वेक्षण (वर्ष)	*सामान्य स्थिति (*पीएस+एसएस) *के अनुसार* एलएफपीआर (प्रतिशत में)		
	शहरी	ग्रामीण	(शहरी +ग्रामीण)
पीएलएफएस, 2017-18	37.0	36.8	36.9
पीएलएफएस, 2018-19	37.7	36.9	37.5
पीएलएफएस, 2019-20	40.8	38.6	40.1
पीएलएफएस, 2020-21	42.7	38.9	41.6
पीएलएफएस, 2021-22	42.2	39.0	41.3
पीएलएफएस, 2022-23	43.4	39.8	42.4
पीएलएफएस, 2023-24	46.8	41.0	45.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24, वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2021-22 और वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2018-19

नोट: 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 – जून 2024 की अवधि से है, इसी प्रकार 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19 और 2017-18 के लिए भी यही अवधि लागू होगी।

(ग)*:* जुलाई 2023 - जून 2024 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से, विभिन्न क्षेत्रों (ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण शहरी संयुक्त) और लिंग (पुरुष, महिला, व्यक्ति) श्रेणियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के राज्यवार अनुमान अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीएलएफएस से सटीक और विश्वसनीय रोजगार आंकड़े सामने आएं। इसे प्राप्त करने के लिए, मजबूत और सुपरिभाषित तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बदलती जरूरतों, फीडबैक और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार करते हैं। प्राथमिक डेटा संग्रहण का कार्य कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) या वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रहण के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सत्यापन तंत्र भी शामिल है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है और इसके परिणामस्वरूप पीएलएफएस की रिपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में भारी कमी आई है। वैचारिक प्रश्नों के समाधान और डेटा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र का पालन किया जाता है। संपूर्ण पीएलएफएस माइक्रोडेटा, जिस पर पीएलएफएस सर्वेक्षण के निष्कर्ष आधारित हैं, पीएलएफएस के वार्षिक प्रसार के साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता अपने स्तर पर भी पीएलएफएस के निष्कर्षों को सत्यापित कर सकते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में अवधारणाएँ और परिभाषाएँ विभिन्न मानकों के अनुरूप तैयार की जाती हैं। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में श्रम सांख्यिकी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ताकि देश के संदर्भ में उनकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का आकलन किया जा सके।

*****

अनुबंध

2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और लिंगों के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में)									
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएलएफएस 2023-24 से सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में)								
	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिला	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी पुरुष	शहरी महिला	शहरी व्यक्ति	(ग्रामीण + शहरी) पुरुष	(ग्रामीण + शहरी) महिला	(ग्रामीण + शहरी) व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आंध्र प्रदेश	59.7	40.7	50.1	59.3	24.5	41.3	59.5	35.8	47.5
अरुणाचल प्रदेश	59.3	53.1	56.3	56.0	34.5	45.1	58.7	49.9	54.4
असम	60.7	38.2	49.6	64.3	25.5	45.0	61.1	36.8	49.1
बिहार	48.1	21.1	34.9	48.2	12.0	30.9	48.1	20.3	34.5
छत्तीसगढ	65.2	50.4	57.8	63.6	27.9	46.4	64.9	46.1	55.5
दिल्ली	54.7	13.8	37.8	54.0	14.5	35.9	54.0	14.5	36.0
गोवा	58.1	21.8	40.5	54.9	23.7	39.5	56.3	22.9	39.9
गुजरात	62.8	44.3	53.8	62.0	23.6	43.7	62.5	35.8	49.6
हरियाणा	51.8	20.2	37.1	56.3	16.7	37.9	53.5	18.8	37.4
हिमाचल प्रदेश	64.9	58.7	61.7	64.2	35.7	51.4	64.8	56.2	60.5
झारखंड	53.1	40.4	46.8	52.1	15.0	34.0	52.9	35.8	44.4
कर्नाटक	60.0	34.6	47.3	59.8	23.6	42.1	59.9	30.5	45.4
केरल	59.7	36.2	47.3	58.4	30.3	43.3	59.1	33.4	45.4
मध्य प्रदेश	63.2	45.4	54.6	58.7	22.3	40.7	62.0	39.4	51.0
महाराष्ट्र	61.0	38.0	49.6	61.0	23.7	43.1	61.0	32.0	46.8
मणिपुर	52.8	36.5	44.6	52.4	35.7	43.9	52.7	36.3	44.4
मेघालय	54.8	48.7	51.7	53.1	37.8	45.1	54.6	47.1	50.7
मिजोरम	51.1	30.5	41.0	49.2	30.2	39.6	50.2	30.4	40.4
नागालैंड	57.3	45.2	51.1	52.0	35.8	44.1	55.7	42.7	49.1
ओडिशा	61.9	40.3	50.8	59.1	24.4	42.0	61.5	38.0	49.4
पंजाब	62.4	27.7	45.2	62.6	19.0	41.4	62.5	24.4	43.7
राजस्थान	56.4	43.0	49.6	56.8	23.5	40.9	56.5	38.0	47.3
सिक्किम	67.1	65.5	66.4	61.1	26.2	46.0	65.7	56.9	61.7
तमिलनाडु	60.4	44.5	52.3	59.2	24.4	41.3	59.8	35.2	47.2
तेलंगाना	61.4	44.0	52.4	57.5	24.5	41.3	59.8	36.5	48.0
त्रिपुरा	64.8	39.1	51.9	57.3	25.9	41.3	63.5	36.8	50.0
उत्तराखंड	56.6	41.8	49.3	55.6	18.6	37.2	56.4	35.9	46.2
उत्तर प्रदेश	54.7	28.1	41.5	56.9	13.5	36.2	55.2	25.2	40.4

पश्चिम बंगाल	63.6	33.7	48.6	64.3	26.8	45.4	63.8	31.7	47.7
अंडमान और उत्तर द्वीप	67.5	44.6	56.5	67.9	30.0	49.3	67.7	38.0	53.3
चंडीगढ़				60.1	25.0	43.5	60.1	25.0	43.5
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	62.1	54.3	58.3	69.9	18.5	47.9	66.7	34.7	52.3
जम्मू एवं कश्मीर	55.7	41.9	49.0	58.2	25.8	42.5	56.2	38.8	47.8
लद्दाख	55.5	46.4	51.3	61.0	26.3	45.0	56.2	43.7	50.5
लक्षद्वीप	73.3	14.5	45.7	56.3	12.4	35.4	61.2	13.0	38.4
पुदुचेरी	58.6	37.1	48.0	58.2	24.4	40.2	58.4	28.9	43.1
अखिल भारतीय	57.9	35.5	46.8	59.0	22.3	41.0	58.2	31.7	45.1

नोट: 1. 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 – जून 2024 की अवधि से है
2. चंडीगढ़ के लिए, संपूर्ण क्षेत्र को शहरी माना जाता है
स्रोत:
वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24

2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और लिंगों के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)									
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएलएफएस 2023-24 से सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में)								
	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिला	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी पुरुष	शहरी महिला	शहरी व्यक्ति	(ग्रामीण + शहरी) पुरुष	(ग्रामीण + शहरी) महिला	(ग्रामीण + शहरी) व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आंध्र प्रदेश	57.4	39.6	48.4	56.0	22.8	38.9	57.0	34.5	45.6
अरुणाचल प्रदेश	56.0	50.7	53.5	50.8	28.2	39.3	55.2	46.8	51.1
असम	58.5	36.9	47.8	60.6	22.5	41.7	58.8	35.3	47.2
बिहार	46.5	20.9	34.0	44.8	10.9	28.7	46.3	20.1	33.5
छत्तीसगढ	64.1	49.7	56.9	59.5	24.9	42.9	63.2	45.0	54.2
दिल्ली	52.8	11.1	35.5	52.8	14.3	35.2	52.8	14.2	35.2
गोवा	54.0	18.8	36.9	52.8	19.3	36.3	53.3	19.1	36.5
गुजरात	62.5	44.2	53.6	60.8	22.8	42.7	61.8	35.4	49.1
हीरयाणा	50.0	19.9	36.0	53.9	16.1	36.4	51.5	18.4	36.1
हिमाचल प्रदेश	62.8	54.6	58.6	61.1	29.2	46.7	62.6	51.8	57.2
झारखंड	52.7	40.4	46.6	49.1	14.1	32.1	52.0	35.6	43.9
कर्नाटक	58.5	34.3	46.4	57.4	22.5	40.3	58.1	29.9	44.1
केरल	57.0	31.8	43.7	55.9	27.0	40.4	56.5	29.5	42.1
मध्य प्रदेश	62.8	45.2	54.3	57.0	21.7	39.6	61.3	39.1	50.6
महाराष्ट्र	59.3	37.5	48.5	58.1	22.3	40.9	58.8	31.2	45.3
मणिपुर	50.3	34.1	42.2	49.5	32.1	40.6	50.1	33.5	41.7
मेघालय	52.8	45.5	49.0	48.4	30.0	38.8	52.2	43.2	47.6
मिजोरम	50.3	30.1	40.5	47.7	29.1	38.2	49.1	29.6	39.5
नागालैंड	54.1	42.6	48.2	46.2	31.7	39.1	51.8	39.6	45.7
ओडिशा	60.1	39.4	49.5	55.8	22.0	39.2	59.4	36.9	47.9
पंजाब	59.2	26.0	42.7	59.6	17.4	39.0	59.4	22.8	41.3
राजस्थान	54.4	41.8	48.0	53.1	21.0	37.7	54.0	36.5	45.3
सिक्किम	65.3	64.5	64.9	60.1	24.4	44.6	64.1	55.7	60.2
तमिलनाडु	58.3	43.3	50.7	57.3	22.9	39.6	57.8	33.9	45.6
तेलंगाना	59.1	42.6	50.6	54.0	21.9	38.3	57.0	34.7	45.7
त्रिपुरा	63.8	38.7	51.1	55.8	24.8	39.9	62.4	36.2	49.2
उत्तराखंड	53.9	40.7	47.3	53.7	16.2	35.1	53.8	34.4	44.2
उत्तर प्रदेश	53.3	27.7	40.6	53.7	12.1	33.8	53.4	24.6	39.2
पश्चिम बंगाल	62.1	33.0	47.5	62.6	25.4	43.9	62.2	30.8	46.4

अंडमान और उत्तर द्वीप	62.8	37.2	50.5	63.1	21.4	42.6	62.9	30.1	47.0
चंडीगढ़				57.7	21.2	40.4	57.7	21.2	40.4
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	59.5	54.3	57.0	68.5	17.8	46.8	64.8	34.4	51.1
जम्मू एवं कश्मीर	53.8	38.9	46.6	55.4	18.8	37.7	54.1	35.1	44.9
लद्दाख	54.3	43.3	49.3	57.5	17.3	39.0	54.8	39.9	47.9
लक्षद्वीप	72.4	7.4	41.9	50.1	9.0	30.5	56.5	8.6	33.8
पुदुचेरी	58.5	35.4	47.1	54.6	22.7	37.6	56.1	27.2	41.1
अखिल भारतीय	56.3	34.8	45.6	56.4	20.7	38.9	56.4	30.7	43.7

नोट: 1. 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 – जून 2024 की अवधि से है
2. चंडीगढ़ के लिए, संपूर्ण क्षेत्र को शहरी माना जाता है
स्रोत:
वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24

2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और लिंगों के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)									
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएलएफएस 2023-24 से सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार यूआर (प्रतिशत में)								
	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिला	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी पुरुष	शहरी महिला	शहरी व्यक्ति	(ग्रामीण + शहरी) पुरुष	(ग्रामीण + शहरी) महिला	(ग्रामीण + शहरी) व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आंध्र प्रदेश	3.8	2.9	3.4	5.5	6.9	5.9	4.3	3.7	4.1
अरुणाचल प्रदेश	5.4	4.6	5.0	9.4	18.1	12.8	6.0	6.2	6.1
असम	3.6	3.5	3.5	5.7	11.8	7.4	3.8	4.1	3.9
बिहार	3.3	0.9	2.6	6.9	9.1	7.3	3.6	1.4	3
छत्तीसगढ	1.6	1.3	1.5	6.5	10.6	7.6	2.6	2.4	2.5
दिल्ली	3.6	19.5	6.0	2.2	1.1	2.0	2.2	1.5	2.1
गोवा	7.1	13.8	8.9	3.8	18.6	8.2	5.2	16.7	8.5
गुजरात	0.5	0.2	0.4	2.0	3.3	2.3	1.1	1.0	1.1
हरियाणा	3.6	1.7	3.1	4.1	3.3	4.0	3.8	2.2	3.4
हिमाचल प्रदेश	3.2	7.0	5.0	4.8	18.2	9.0	3.4	7.8	5.4
झारखंड	0.8	0.0	0.5	5.8	5.8	5.8	1.8	0.5	1.3
कर्नाटक	2.5	0.9	1.9	4.1	4.4	4.2	3.1	1.9	2.7
केरल	4.6	12.1	7.6	4.2	10.9	6.7	4.4	11.6	7.2
मध्य प्रदेश	0.6	0.3	0.5	2.9	2.6	2.8	1.1	0.7	0.9
महाराष्ट्र	2.8	1.1	2.2	4.9	6.0	5.2	3.7	2.7	3.3
मणिपुर	4.7	6.6	5.5	5.6	10.3	7.5	5.0	7.7	6.1
मेघालय	3.7	6.6	5.1	8.9	20.6	14.0	4.4	8.2	6.2
मिजोरम	1.5	1.0	1.3	3.2	3.9	3.4	2.2	2.4	2.3
नागालैंड	5.5	5.8	5.7	11.1	11.6	11.3	7.0	7.1	7.1
ओडिशा	2.9	2.0	2.6	5.6	9.7	6.8	3.3	2.7	3.1
पंजाब	5.1	6.2	5.4	4.8	8.6	5.6	4.9	6.9	5.5
राजस्थान	3.5	2.7	3.2	6.5	10.9	7.7	4.3	4.0	4.2
सिक्किम	2.7	1.6	2.2	1.7	6.9	3.0	2.5	2.1	2.3
तमिलनाडु	3.5	2.7	3.1	3.2	6.0	4.1	3.4	3.8	3.5
तेलंगाना	3.7	3.1	3.5	6.0	10.4	7.3	4.6	5.0	4.8
त्रिपुरा	1.6	1.2	1.4	2.7	4.4	3.2	1.7	1.6	1.7
उत्तराखंड	4.8	2.7	3.9	3.5	13.0	5.8	4.5	4.0	4.3
उत्तर प्रदेश	2.6	1.5	2.2	5.7	11.0	6.7	3.3	2.5	3
पश्चिम बंगाल	2.3	2.3	2.3	2.6	5.0	3.3	2.4	3.0	2.6
अंडमान और उत्तर द्वीप	6.9	16.6	10.6	7.0	28.6	13.5	7.0	20.9	11.8

चंडीगढ़				3.9	15.3	7.1	3.9	15.3	7.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.2	0.0	2.3	2.0	3.8	2.3	2.9	1.1	2.3
जम्मू एवं कश्मीर	3.5	7.1	5.0	4.8	27.2	11.4	3.8	9.7	6.1
लद्दाख	2.0	6.6	3.9	5.6	34.4	13.4	2.6	8.8	5.1
लक्षद्वीप	1.2	49.1	8.3	11.1	27.2	13.8	7.7	34.1	11.9
पुदुचेरी	0.1	4.7	1.9	6.3	6.9	6.5	3.9	5.9	4.6
अखिल भारतीय	2.7	2.1	2.5	4.4	7.1	5.1	3.2	3.1	3.2
नोट: 1. 2023-24 का तात्पर्य जुलाई 2023 – जून 2024 की अवधि से है 2. चंडीगढ़ के लिए, संपूर्ण क्षेत्र को शहरी माना जाता है *स्रोत:* *वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24*									